25 जनवरी 2017 को 15वीं विशेष सशस्त्र बल कॉम्पलेक्स, इन्दौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

1. 15वीं विशेष सशस्त्र बल कॉम्पलेक्स, इन्दौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के उद्घाटन और अन्य चार वाहिनियों जहां कि Video Conferencing से उद्घाटन किया जाना है, के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी जी एवं मध्यप्रदेश के कौशल विकास मंत्री श्री दीपक जोशी यहां उपस्थित हैं।

2. मध्यप्रदेश पुलिस के कर्मचारियों के शिक्षित एवं बेरोजगार परिजनों को कौशल विकास द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संबंधित विभाग, मध्यप्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय का प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र की स्थापना का यह प्रयास सराहनीय है।

3. भारत की आबादी का लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा हैं और वे 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह वक्त की मांग है कि युवा शक्ति के रूप में मिले इस जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) की ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक एवं सृजनात्मक रूप से करें। हम इस युवा शक्ति को पर्याप्त कौशल एवं क्षमता प्रदान करके उसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दक्ष श्रम संसाधन बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य भारत को विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ कुशल वर्कफोर्स के समूह के रूप में विकसित करना है।

4. सन् 2025 तक तो भारत की 70 प्रतिशत जनता working age की होगी और साथ–ही–साथ तेज गति से हो रहे विकास के कारण यह अनुमान है कि भारत में बहुत तेजी से नई नौकरियों का सृजन होगा। परंतु, Research study से यह पता चला है कि skill की कमी के कारण इनमें से अधिकांश लोग unemployable होंगे और इसके चलते Industries की productivity घटेगी जिससे उत्पादन की लागत बढ़ सकती है।

आज हमारे सामने चीन का उदाहरण है जहां अच्छी skill training के कारण मजदूरों एवं मशीनों की productivity सबसे ज्यादा है, साथ ही उत्पादन लागत भी कम है। इसलिए, दुनिया के तमाम बाजारों पर Chinese Goods का वर्चस्व है।

5. ऐसा अनुमान है कि हमें सन् 2022 तक 50 करोड़ और अधिक लोगों को विभिन्न vocational training skills में प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कम शिक्षा या अशिक्षा हमारे skill development programme में entry का barrier न बन जाए क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि vocational training school में admission के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। इससे बहुत बड़ी संख्या में अशिक्षित एवं अल्प शिक्षित व्यक्तियों का इस प्रोग्राम से वंचित रह जाने का खतरा है।

6. Skill development के महत्व को इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2 लाख skilled drivers की कमी है वहीं युवा वर्ग रोजगार की तलाश में इधर–से–उधर भटक रहा है। जहां एक ओर ड्राइवरों की कमी है वहीं दूसरी ओर वर्तमान कार्यरत ड्राइवरों में पर्याप्त कौशल एवं कुशलता के अभाव होने से दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में होती हैं और इसके चलते प्रतिवर्ष बहुत अधिक जान–माल की क्षति होती है और देश को भी आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ता है। मुझे खुशी है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 10 लाख व्यक्तियों को ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षण देने और उनको माइक्रो–इंटरप्रेन्योर्स का लक्ष्य रखा है। यह न केवल उनको रोजगार प्रदान करेगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी इससे काफी कमी आएगी।

6. देश के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने एवं तेज आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपने मानव संसाधन को विशिष्ट कौशल से युक्त करें। विशेषज्ञों का यह कहना है कि भविष्य में निर्माण क्षेत्र में, आई.टी. क्षेत्र की तुलना में छह गुना अधिक नौकरियों का सृजन

होगा। परंतु जिन राज्यों में निर्माण के क्षेत्र में ज्यादा कार्य होना है, वहां पर भी आई.टी. सेक्टर और उससे संबंधित सेवाओं में skill training पर ही ज्यादा focus है। हैरानी की बात यह भी है कि construction के क्षेत्र में सबसे ज्यादा unskilled persons (83%) काम कर रहे हैं। अतः, इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य उचित सहयोग, समन्वय और सहमति आवश्यक है।

7. भारत सरकार की बहुद्देशीय योजनाएं जैसे स्किल डेवलपमेंट, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा मुद्रा योजना इत्यादि इस उद्देश्य से लाईं गईं हैं कि लोग इससे न केवल सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए ही प्रेरित हों बल्कि स्वयं अपना व्यवसाय या पेशा शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इन योजनाओं के मूल में ही उद्यमिता है। यह सारा कार्य केवल सरकार पर निर्भर होकर नहीं किया जा सकता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लेना होगा और पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप मॉडल (PPP Model) का अधिक–से अधिक उपयोग करना होगा।

8. हमें job oriented शिक्षा प्रणाली की बजाय vocational oriented शिक्षा प्रणाली पर भी उचित बल देना चाहिए। साथ ही, समाज और सामाजिक सोच में बदलाव की भी अपेक्षा है। हमारे समाज में vocational training को परंपरागत रूप से कम महत्व एवं सम्मान प्राप्त है। ऐसा देखा गया है कि समाज में White collar job करने वालों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है जबकि ज्यादातर छोटे–बड़े शहरों में mason, electrician, plumber, fitter, mechanic, drivers इत्यादि की अत्यन्त आवश्यकता है। दिल्ली जैसे महानगर में तो उनकी सेवाओं के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और दूसरी ओर चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बीएससी, एमएससी, एमबीए, कहीं–कहीं तो पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदकों को आवेदन करते हुए पाया गया है। यह एक विरोधाभास है।

9. इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया है जिसका उद्देश्य युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें दक्ष मानव संसाधन बनाना है। ऐसे प्रशिक्षण के पश्चात् युवा या तो स्वरोजगार कर सकते हैं या फिर अपनी योग्यतानुसार किसी प्रतिष्ठान में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दोनों अवस्था में यह राष्ट्र निर्माण का कार्य होगा, विकास का कार्य होगा, साथ ही उनकी आर्थिक उन्नति भी होगी।

10. Skill development programme तैयार करते हुए हमें भविष्य की चुनौतियों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे टेक्नोलॉजी के चलते विश्व में आ रहे तेजी से बदलाव के कारण नौकरियां परम्परागत आर्थिक गतिविधियों से हटकर नए सेक्टरों जैसे सर्विस सेक्टर, आई.टी. सेक्टर और अन्य technology related sectors में उत्पन्न होंगी। हमें इसका अभी से अनुमान लगाकर हमारे युवाओं को उन सभी आवश्यक skills में प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे न केवल भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें बल्कि हमारा देश इस क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सके।

11. युवाओं के सशक्तिकरण से ही भारत को समृद्ध एवं विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सकता है। वर्तमान एवं भविष्य, दोनों का सुनहरा पल अब युवाओं के हाथों में हैं एवं यह उनके कौशल एवं दक्षता पर ही निर्भर करेगा। Sustainable Development Goals में भी इन बातों को प्रमुखता से लिया गया है तथा सन् 2030 तक सभी को रोजगार दिलाने का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र ने रखा है।

12. प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों से प्राप्त प्रशिक्षण योजना के तहत विभिन्न प्रकार की दक्षता से युक्त, आर्थिक रूप से सशक्त एवं विचारों से सकारात्मक युवा समूह न केवल रोजगार पा रहे हैं बल्कि स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। यह भी खुशी की बात है कि पारंपरिक प्रशिक्षण के साथ–साथ नए–नए संकायों में उन्नत प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप बेहतर श्रम संसाधन हमारे समक्ष हैं।

13. इस योजना के तहत उन सरकारी भवनों, स्कूलों और ऑडिटोरियम परिसर इत्यादि का बढ़िया उपयोग सुनिश्चित हो रहा है। वास्तव में, देश के उस वंचित श्रेणी के लोगों के लिए प्रशिक्षण का उत्तम अवसर है, जो विषमता, गरीबी एवं बेरोजगारी से त्रस्त हैं और अपने विकास का कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण से भारत में आमूल–चूल परिवर्तन हो सकता है।

14. आज आधुनिक युग में युवाओं में ब्रांड के प्रति बहुत ललक है। उन्हें ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी एवं कारें इत्यादि खरीदना पसंद है। हरेक ब्रांड अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। हमें याद रखना चाहिए कि वह ब्रांड कहीं न कहीं कुशल कारीगरों की कुशलता के कारण ही उस मुकाम तक पहूंची है। अगर हम अपने हुनर और कौशल को विकसित करेंगे तो हम न केवल उस व्यक्ति बल्कि समूचे समाज के जीवन–स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे और **Make in India** को एक सशक्त ब्राण्ड बना सकेंगे।

15. **Vocational training has the power to transform India into the skill capital of the world.** मेरे संसदीय क्षेत्र इन्दौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के लिए मैं केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन दोनों को धन्यवाद देती हूं।

जय हिन्द।

———————